प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक - 39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 02 - 09 अक्तूबर 2017 मूल्य पांच रूपए

भ्रष्टाचार पर भाजपा को भी देना होगा जवाब

शिमला/शैल। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने भी बिलासपुर रैली में वीरभद्र और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए यहां तक तंज कसा कि कांग्रेस में तो सोनिया-राहुल से लेकर वीरभद्र तक सब ज़मानत पर हैं। इसलिये अब वक्त आ गया है कि इनको सत्ता से बेदखल करके ज़मानत से मुक्त कर दिया जाये। मोदी से पहले संबित पात्रा,

रविशंकर प्रसाद तथा सुधांशु मित्तल जैसे नेता भी इस भ्रष्टाचार को निशाना बना चुके हैं। स्मरणीय है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी मोदी ने सुजानपुर में एक रैली में वीरभद्र के इसी भ्रष्टाचार पर निशाना साधा था और प्रदेश की जनता को यह बताया था कि वीरभद्र के तो पेड़ों पर भी पैसे उगते हैं। लोगों ने उस वक्त मोदी पर विश्वास किया और लोकसभा की चारों सीटें भाजपा को दे दी थी। ऐसा इसलिये हुआ था क्योंकि लोगों को लगा था कि अब निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कारवाई सामने आयेगी लेकिन आज मोदी को सत्ता में आये करीब चार साल होने वाले हैं लेकिन इन चार सालों में वीरभद्र के मामलों में कोई ठोस कारवाई देखने को नही मिली है। केवल सीबीआई इसमें अदालत में आरोप पत्र फाईल कर पायी है। जिस पर अभी अगली कारवाई शुरू होनी है। ईडी इस मामले में दो अटैचमैन्ट आदेश जारी करके वीरभद्र के एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन वीरभद्र के खिलाफ ऐसी कोई कारवाई नही कर पायी है। अब इन मामलों में यह गंध आने लगी है कि भाजपा और मोदी को यह भ्रष्टाचार के मुद्दे केवल चुनावों के लिये ही चाहिये अन्यथा भ्रष्टाचार पर कतई गंभीरता नहीं है।

आज मोदी से लेकर केन्द्र के दूसरे नेताओं तक को हिमाचल में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिये वीरभद्र के ज़मानत पर होने को मुद्दा बनाना पड़ा है लेकिन इसी के साथ यह भी गौरतलब है कि आज प्रदेश भाजपा के भी कई बड़े नेता ज़मानत पर हैं। प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, डा. राजीव बिन्दल और विरेन्द्र कश्यप जैसे सारे नेता अपराधिक मामलों में स्वयं ज़मानत पर हैं। प्रदेश की जनता इन मामलों के बारे में अच्छी तरह जानती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के एम्ज़ प्रकरण को लेकर जो कुछ दस्तावेज यथावत् के माध्यम से जनता के सामने आ चुके हैं आज प्रदेश की जनता इन मामलों में भी बराबर का हिसाब मांगेगी। एम्ज़ के मामले में तो वहां के डाक्टरों की ओर से प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव को शिकायत भेजी गयी है जिस पर अभी तक कोई कारवाई नही हुई। बल्कि चर्चा तो यहां तक है कि इस मामले में यथावत् की टीम पर भी संघ कार्यालय में मन्त्री को बुलाकर इन मामलों को और आगे न बढ़ाने का आग्रह किया गया है। अब चुनाव के दिनों में यह सब सामने आयेगा कि किसके खिलाफ कितने मामले हैं। क्योंकि यह भी चर्चा है कि प्रदेश भाजपा के एक सांसद के खिलाफ उसी के चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक करीब एक दर्जन एफआईआर दर्ज हैं। अभी पिछले दिनों शिमला के जनेड़घाट में एक टूरिस्ट रिजार्ट से जो कॉल गर्ल्ज़ पकड़ी गयी थी उस रिज़ार्ट की ज़मीन के मालिक भी एक सांसद ही हैं और उन्ही का भाई इस टूरिस्ट कंपनी का निदेशक है। इस मामलें की जांच के छींटे तो कानून के मुताबिक सांसद और उसके भाई तक पहुंचते हैं। संभवत: इसी कारण से इस मामले की जांच को लेकर कहीं से भी कोई आवाज़ नही उठ रही है।

बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों पर भाजपा का अपने शासनकाल के दौरान भी रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नही रहा है। वर्ष 2003 से 2007 तक जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भाजपा ने बतौर विपक्ष चार आरोप पत्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल को सौंपे थे। 2007 में जब भाजपा सत्ता में आ गयी तब यह आरोप पत्र विजिलैन्स को जांच के लिये भेजे गये थे। इन आरोप पत्रों पर प्रारम्भिक जांच करने के बाद विजिलैन्स ने इन्हें अगली कारवाई के निर्देशों के लिये सरकार को भेजा था। लेकिन इन मामलों पर सरकार की ओर से कारवाई के कोई निर्देश नही गये और विजिलैन्स ने

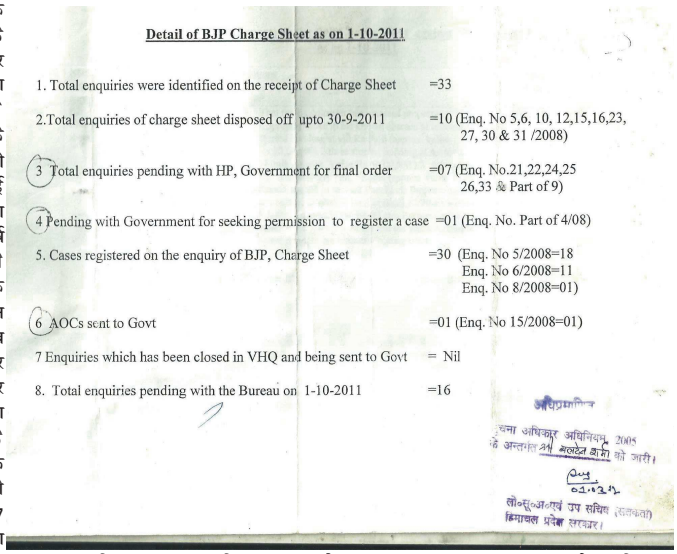

Detail of BJP Charge Sheet as on 1-10-2011

1. Total enquiries were identified on the receipt of Charge Sheet	=33
2.Total enquiries of charge sheet disposed off upto 30-9-2011	=10 (Enq. No 5,6, 10, 12,15,16,23, 27, 30 & 31 /2008)
3 Total enquiries pending with HP, Government for final order	=07 (Enq. No.21,22,24,25 26,33 & Part of 9)
4 Pending with Government for seeking permission to register a case	=01 (Enq. No. Part of 4/08)
5. Cases registered on the enquiry of BJP, Charge Sheet	=30 (Enq. No 5/2008=18 Enq. No 6/2008=11 Enq. No 8/2008=01)
6 AOCs sent to Govt	=01 (Enq. No 15/2008=01)
7 Enquiries which has been closed in VHQ and being sent to Govt	= Nil
8. Total enquiries pending with the Bureau on 1-10-2011	=16

भी अपने स्तर पर आगे कुछ नही किया। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि भ्रष्टाचार पर सौंपे जाने वाले आरोप पत्र केवल चुनावों में भुनाने के लिये होते हैं कारवाई के लिये नहीं। इस हमाम में कांग्रेस का आचरण भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अब तक यही फैसला आर सी एस से नही आ सका है कि एच पी सी ए कंपनी है या सोसायटी जबकि एच पी सी ए को लेकर बने सारे मामलों में पहला मूल प्रश्न यही रहेगा।

सरकार की हैरिटेज पॉलिसी पर सी पी एम ने उठाये सवाल

शिमला/शैल। कसुम्पटी विधानसभा हलके से वामपंथी प्रत्याशी व पूर्व आईएफएस अफसर कुलदीप सिंह तंवर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो कि बुशहैर राजपरिवार से हैं के खिलाफ तीखा इल्जाम लगाया है। बीते रोज वीरभद्र सिंह केबिनेट ने हेरिटेज पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसे वामपंथियों ने राजे-रजवाड़ों के जर्जर हो चुके भवनों को सरकारी खजाने से सजाने-संवारने का इंतजाम करार दिया है।

उन्होंने कहा कि पहले राजशाही ने जनता का शोषण करके अपने आलीशान महल खड़े किए और आज जब उनके पास इस ढांचे के रखरखाव के लिए न तो आज बेगार प्रथा रही और न ही जनता के शोषण करने की ताकत रही तो वे पिछले दरवाजे से जनता का पैसा अपने महलों को संवारने के लिए लगाने की साजिश रच रहे हैं।

वामपंथी प्रत्याशी व पार्टी सचिव

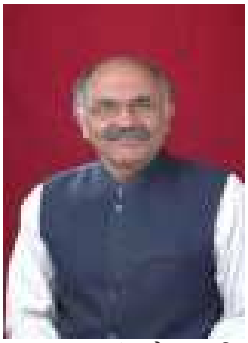

मण्डल सदस्य तंवर ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर और विरासत केवल राजे-रजवाड़ों की या जनता की मेहनत और बेगार से बने उनके राजमहलों की ही नहीं है बल्कि एक विरासत मेहनतकश अवाम की भी रही है। हमारे कारीगर कुम्भकार, लोहार, छड़ियां बनाने वाले, पारम्परिक वाद्ययंत्र बनाने वाले, काष्ठकला के कारीगर सहित आज सभी तरह के कारीगर आज संरक्षण के अभाव में गरीबी और बदहाली से जूझ रहे हैं।

मशोबरा खण्ड के मोहनपुर, थोटी आदि गांवों से छड़ियां बनाने वाले लोग आज बदहली का जीवन जी रहे हैं। शिमला का लक्कड़ बाजार पूरे देश में लकड़ी की कारीगरी की तरह-तरह की चीजों के लिए प्रसिद्ध था जो आसपास के गांवों से बनकर आती थी लेकिन अब न तो लोगों को जंगलों से उन चीजों को बनाने के लिए लकड़ियां लेने की इजाजत है और न ही उन्हें किसी तरह का प्रोत्साहन दिया गया।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें

कार्यालय दूरभाष – 0177 – 2805015, **मो.** 8988587014, **मो.** 9418069978, **मो.** 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, **वेबसाईट** – www.shailsamachar.co.in

पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

गौ माता की रक्षा होगी तो बचेगा किसानः राज्यपाल

शिमला/शैल। शिमला के निकट जाठिया देवी में क्योंथल सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोगों से आह्वान किया कि वे गाय के महत्व को समझकर इसका पालन करें। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय के माध्यम से देश के किसानों को बचाया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को ऊंचा स्थान प्राप्त है और इसे माता का दर्जा दिया गया है। उन्होंने चिंता जताई कि भौतिकतावाद के इस युग में गाय को पराया कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज वैज्ञानिकों ने भी गाय पर अनेक शोध कर इसके दूध, गोबर, गौमूत्र को अद्भुत पाया है। उन्होंने कहा कि हमारे हर धार्मिक ग्रंथ में गाय का उल्लेख है और इसका वर्णन मनुष्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह हमारी कमजोरियों का ही परिणाम है कि इसे सड़कों पर छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसके एक ग्राम गोबर में करीब 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाये जाते हैं, जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि एक देसी गाय से 30 एकड़ भूमि पर कृषि की जा सकती है। इसी तरह गौमूत्र भी कई मायनों में फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इसका गौमूत्र इतना प्रभावी है कि आयुर्वेद में जहरीली दवाओं का शोधन भी इसी से किया जाता है।

उन्होंने क्योंथल सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान संस्था को गौशाला के लिए 51 हजार रुपये देने की घोषणा भी की।

सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान संस्था क्योंथल के प्रधान मदन ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने कामनापूर्णी गौशाला समिति टुटू में माला-पूर्णिमा, शरद-पूर्णिमा और वाल्मीकि जयन्ती पर आयोजित समरसता दिवस के मौके पर गाय के नस्ल सुधार पर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में देसी गाय पर आधारित खेती का म डल तैयार किया गया है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि जात-पात हमारी मानसिकता का परिणाम है और जात-पात के भेद ने समाज को तोड़ने का ही कार्य किया है। वेदों में वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर निर्धारित किया है और मानव जाति का ही उल्लेख किया गया है। उन्होंने लोगों से अंधविश्वास से बचने और समाज से पाखंड को दूर करने की अपील की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कामनापूर्णी गौशाला के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

कामनापूर्णी गौशाला समिति टुटू के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर डी.ए.वी. स्कूल टुटू और एस.डी. स्कूल गंज शिमला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

स्वच्छता बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यकःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि 'शद्धीकरण' को हमारे धर्म में पांच तत्वों में एक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे संतों ने आन्तरिक तथा बाह्य स्वच्छता के बारे में कहा है, इसलिये जीवन के लिए स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कुरूक्षेत्र में एनआईटी कुरूक्षेत्र द्वारा विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान एवं रागीरी के सहयोग से आयोजित 'कालिया मर्दन एवं स्वच्छ गृह' व्याख्यान के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सम्मान व प्रतिष्ठा तथा स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता अभियान की शुरूआत की है। राज्यपाल ने कहा कि यह नागरिक समाज का दायित्व है कि हम ईमानदारी के साथ देश को स्वच्छ बनाने में योगदान करें।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान में शामिल (ब्रॉड एम्बेस्डर) नवरतनों में एक पदम विभूषण डा. सोनल मानसिंह को सम्मानित किया।

डा. सोनल मानसिंह ने इस अवसर पर कहा कि सफाई हमारी नैतिकता से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने धर्म की दृष्टि से रोजमर्रा के जीवन में सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला।

एनआईटी के निदेशक पदम डा. सतीश कुमार ने संस्थान में वर्ष के दौरान आयोजित की गई स्वच्छता गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

रागिरी के संचालक शिवेन्द्र कुमार ने कहा कि उनका संगठन भी स्वच्छता अभियान सहित अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के निदेशक डा. रामेन्द्र सिंह ने स्वच्छता अभियान में किए जा रहे संस्थान के प्रयासों के बारे अवगत करवाया।

अधिष्ठाता एनआईटी छात्रा कल्याण प्रो. सत हंस ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कामाख्या कलापीठ के कलाकारों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी।

विशेष अभियान के दौरान प्रदेश में 65016 आवेदन प्राप्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव-2017 के दृष्टिगत 16 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2017 तक मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए चलाए गए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान के दौरान राज्य में कुल 65,016 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 52,155 नए मतदाताओं ने फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए फार्म संख्या-6 प्रस्तुत कर अपना पंजीकरण करवाया। नए मतदाताओं में अधिकांश 18-19 वर्ष आयुवर्ग के युवा हैं।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी.के. रतन ने कहा कि कुल आवेदन पत्रों में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए 6,251 फार्म, शुद्धिकरण के लिए 5,703 फार्म जबकि निर्वाचन सभा क्षेत्र के अन्दर नाम हस्तांतरित के लिए कुल 907 फार्म प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 2,365 एएसडी यानि अनुपस्थित/हस्तांतरित/मृतक मतदाता हैं जिनकी अलग से सूची तैयार की गई है, लेकिन इनके नाम मतदाता सूची से काटे नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 सितम्बर, 2017 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में कुल 49,05,677 मतदाता पंजीकृत हैं।

रतन ने कहा कि मतदाता फार्म संख्या-6, 7, 8 व 8ए नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन पहले तक संबंधित बूथ स्तर के अधिकारियों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के पास जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने पात्र मतदाताओं से फोटो पहचान पत्र बनवाने के लिए अपना पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटवाने, शुद्धिकरण अथवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नाम हस्तांतरित करवाने के संबंध में भी मतदाताओं से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में चलाया गया अभियान सफल रहा है। अभियान के दौरान युवाओं ने फोटो पहचान पत्र बनवाने में काफी उत्साह दिखाया और अपना पंजीकरण करवाया। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों ने घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं को फार्म उपलब्ध करवाकर उनका पंजीकरण किया और साथ ही युवाओं तथा आम लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान कर उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश ए.के.गोयल ने दिया भारतीय संविधान के विभिन्न पक्षों पर वक्तव्य

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने समाज को भारतीय संविधान के विभिन्न पक्षों से अवगत करवाने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 'भारतीय संविधान के विभिन्न पक्ष' पर वक्तव्य का आयोजन किया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल ने आयोजन का उद्घाटन किया।

न्यायधीश ए.के. गोयल ने अपने उद्घाटन सम्बोधन में शिमला शहर को आकर्षण का केन्द्र बताया तथा सादगी के लिए प्रदेश के लोगों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण सभी को न्याय प्रदान करने में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। उन्होंने संविधान सभा में डॉ. बी.आर अम्बेडकर द्वारा दिए गए समापन भाषण का उदाहरण देते हुए कहा कि डॉ. अम्बेडकर महानतम कानूनविद्व थे। उन्होंने कहा कि संविधान को अपनाने का निर्णायक उद्देश्य सभी के लिए न्याय सुनिश्चित बनाना था जो कि भारतीय संविधान की आत्मा है तथा इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया।

'कानून के शासन' के बारे में बात करते हुए न्यायधीश गोयल ने कहा कि महाभारत तथा रामायण जैसे महान ग्रन्थों में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते है जिसके माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार उस समय समाज में कानून व्यवस्था कायम रखी गई। उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक काल के दौरान कुशल शासन के लिए उपयुक्त कानून बनाए गए थे।

न्यायधीश गोयल ने कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में कानून व्यवस्था थी लेकिन आम लोगों न्याय प्रदान नहीं होता था। उन्होंने कहा कि देश की प्रथम व सर्वोच्च जिम्मेवारी है कि लोगों के कल्याण व न्याय को सुनिश्चित बनाए, जो कि संविधान का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि संविधानसभा में महान न्यायधीशों ने परिचर्चा की कि किस तरह समानता, आजादी व भाईचारे के सिद्धान्तों व सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी व्यक्ति को नायक मानकर अनुसरण न करें बल्कि संविधान की सच्ची भावना को समझकर उसका अनुसरण करें।

उन्हांने व्यतव्य श्रृंखला के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सराहना की।

अपने स्वागत सम्बोधन में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश संजय करोल ने कहा कि न्यायधीश गोयल एक महान विद्वान है तथा उन्होंने वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कई निर्णायक निर्णय दिए हैं।

इस अवसर पर न्यायधीश त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायधीश सुरेश्वर ठाकुर, न्यायधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायधीश अजय मोहन गोयल, न्यायधीश सन्दीप शर्मा, न्यायधीश सी.बी. बरोवालिया, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वी. के.शर्मा, राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पी.एस. राणा, भारत के सहायक सोलिस्टर जनरल के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार संघ के अध्यक्ष, वरिष्ठ वकील तथा बार एसोसिएशन के सदस्य, सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश विधि सेवाएं के सदस्य सचिव व प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अकादमी के निदेशक व उप निदेशक, 300 विधि छात्र तथा विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी आयोजन में भाग लिया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDERS'

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD Palampur on behalf of the Governor of H.P for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on 03-11-2017 up to 11.00 AM. And the same shall be opened on the same day at 11.30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on 02-11-2017 up to 4.00 P.M and the application for issue of tender form shall be received on 01-11-2017 up to 12.00 noon. The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender form
1	Multipourpose Hall at G.S.S. Khera. (S.W:- P/F False ceiling saint Gobain Gyproc MFT Tile).	9,94,124/-	20000/-	Two Months	350/-
2	C/O Maranda Dehan Punner road Km. 0/00 to 6/300. (S.W:- C/O R/Wall at R.D 6/160 to 6/190).	1,91,674/-	3900/-	Two Months	350/-
3	Multipourpose Hall at G.G.S Khera. (S.W:- P/F Wall panels of size .60 X 1.20) for sound proofing).	5,87,943/-	12000/-	Two Months	350/-
4	A/R & M/O type-I & III Residential Accomodation PWD Qtrs at (Lohna) Palampur. (S.W:- C/O Breast wall & plinth protection & U-Shape drain).	3,34,001/-	6700/-	Three Months	350/-
5	R/D on link road to village Kandi to Thala to Malenta. (S.W:- R/Wall & wire create at Rd 0/275 to 0/295 & 1/640 to 1/655).	4,93,190/-	10000/-	Three Months	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.
1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration.
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand . Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-3069/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव

शिमला/शैल। राष्ट्रीय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जिला मण्डी के पब्ल मैदान में आयोजित रैली में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने वीरभद्र सिंह को 7वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों का आहवान किया।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में हुए विकास की तुलना की तथा प्रदेश में शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ लगभग 70,000 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय कांग्रेस उपाध्यक्ष ने वीरभद्र सिंह को सही मायनों में फकीर बताया तथा लोगों से उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने को कहा।

राहुल गांधी ने 'विजय से विकास' रैली के साथ ही प्रदेश में चुनाव अभियान का आरम्भ किया तथा कहा कि हमें एकजुट होकर प्रदेश में वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर एक बार फिर कांग्रेस सरकार को विजयी बनाना होगा ताकि राज्य निरंतर प्रगति कर सके।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार तथा नरेन्द्र मोदी की नीतियों की आलोचना की तथा उन्हें जीडीपी में गिरावट के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में आई 2 प्रतिशत की गिरावट आर्थिक सुधारों की अव्यवस्था को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए परेशानी बनने वाले वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) को लोगों पर अकारण थोपा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वस्तुए व सेवाएं और भी मंहगी हो गई है तथा यह निर्णय लघु व सीमान्त व्यापारियों के हितों को दरकिनार करते हुए जल्दी में लिया गया है।

उन्होंने कहा कि समग्र देश में एक कर के वजाय एनडीए सरकार ने पांच विभिन्न प्रकार के कर लगाकर अर्थव्यवस्था को बुरी तरह हिला दिया है, जिसमें 28 प्रतिशत का कर लगाने से शुरूआत की गई है। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका था।

उन्होंने केन्द्र सरकार की विमुद्रीकरण के लिए भी आलोचना की तथा कहा कि इस फैसले ने लोगों को चौंकाया है तथा परेशानियां और भी बड़ी है।

राहुल गांधी ने जनसैलाब के

प्रति अपनी भवनाएं जाहिर करते हुए कहा कि या तो रैली के दौरान उनके उपर भी छत न होती या फिर सभी लोगों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए उपयुक्त इन्तजाम होते।

राहुल गांधी ने दोनों राज्यों के बीच तुलना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये का मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है जबकि गुजरात में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि गत पांच वर्षों में हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने 15000 स्कूल खोले व स्तरोन्नत किए जबकि गुजरात में 13000 हजार स्कूल बन्द किए गए है।

उन्होंने कहा कि गत पांच वर्षों में हिमाचल सरकार ने प्रदेश में चार मैडिकल कॉलेज व 57 डिग्री कॉलेज खोले हैं जबकि गुजरात में केवल 25 डिग्री कॉलेज खोले गए व कोई भी मैडिकल कॉलेज नहीं खोला गया। उन्होंने विकास के नाम पर गुजरात के लोगों को बेवकूफ बनाने वाले गुजरात विकास मॉडल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के निर्धन लोगों को गृह निर्माण के लिए 1.30 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जबकि गुजरात में यह आंकड़ा मात्र 70,000 रुपये है। प्रदेश में सामाजिक कल्याण पैंशन के अन्तर्गत 700 रुपये मासिक प्रदान की जा रही है जबकि गुजरात में यह राशि केवल 450 रुपये मासिक है।

राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार ने युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार प्रदान करने के वचन को भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में भी असमर्थ रही है तथा केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने की विफल नीतियों के चलते सैंकड़ों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए लोगों का उनका समर्थन करने व भरपूर प्यार देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया तथा कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ उनके पारिवारिक सम्बन्ध हैं तथा लोगों के साथ उन्हें बेहद स्नेह है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग उनके परिवार के सदस्य है। उन्होंने कहा कि लोगों के मार्गदर्शन व सुझावों के फलस्वरूप ही हिमाचल प्रदेश एक लम्बा सफर तय कर देश का सबसे विकसित राज्य बन पाया है। उन्होंने पण्डित जवाहर लाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक पूरे गांधी परिवार को हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कार्य करने का श्रेय दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य के 95 प्रतिशत शैक्षणिक संस्थान प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान खोले गए हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान लगभग 230 स्वास्थ्य संस्थान खोले व स्तरोन्नत किए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग पर एम्स के लिए भूमि उपलब्ध करवाई है लेकिन भाजपा के प्रादेशिक नेता दावा करते हैं कि केन्द्र सरकार ने एम्स को स्वीकृति प्रदान की तथा इसके लिए धन उपलब्ध करवाया है।

''मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि विकास कार्यो के लिए धन में राज्यों का हिस्सा राज्यों का दें और इसी तरह एम्स के लिए भी धन किसी की निजी जेब से नहीं दिया गया है बल्कि यह धन भारत सरकार द्वारा राज्यों के हिस्से के तौर पर दिया जाता है और धन को प्राप्त करने का राज्यों को पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार केन्द्र शासित प्रदेशों को आवश्यक धन देने की बात का बखान करती है तो यह उचित है क्योंकि केन्द्र शासित प्रदेश केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं लेकिन राज्य सरकारों के हक के मामले में ऐसा कहना उचित नहीं है।''

उन्होंने कहा कि केन्द्र में चाहे कोई भी सरकार हो, यह केन्द्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्यों को उनके लिए निर्धारित किया गया धन अवश्य मिले ।

उन्होंने कहा कि यद्यपि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सम्मान करते हैं लेकिन वह देश में ऐसी नीतियां लागू कर नहीं कर सकते जो निरंकुशता की ओर अग्रसर हों। उन्होंने कहा कि वस्तु व सेवा कर ने भारतीय आर्थिकी की कमर तोड़ कर रख दी है ।

प्रदेश की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होने बताया कि राज्य के निर्माण के समय मात्र 288 किलोमीटर सड़कें थीं, जो बढ़कर आज 37 हजार किलोमीटर हो गई हैं। राज्य ने 100 प्रतिशत विद्युतिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक गांव में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है और आज राज्य में 137 डिग्री कालेज हैं जिनमें से 57 इस कार्यकाल में खोले गए हैं ताकि उच्च शिक्षा सुदूर गांवों तक भी पहुँच सके।

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने सभी चुनावी वायदे पूरे करने में नाकाम रही है जो उन्होंने पिछले तीन वर्षो के दौरान देश की जनता के साथ किए थे।

स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी का स्वागत किया और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने धन्यवाद किया ।

इस अवसर पर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे, राज्य सभा सदस्य आनन्द शर्मा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं हिमाचल की सह-प्रभारी रंजीता रंजन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्द्र सुक्खू तथा विप्लव ठाकुर ने भी अपने विचार रखे।

मतदाता सूची से हटाये गये नामों पर आपत्ति बारे सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें दावा

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा साधारण निर्वाचन-2017 के दृष्टिगत मतदाता सूचियों को नवीनतम व अद्यतन बनाए रखने के लिए एक जुलाई से 28 जुलाई, 2017 तक मतदाता सूचियां का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया गया था। पुनरीक्षण कार्य के दौरान 1,25,556 मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए तथा पहले से ही पंजीकृत 47,523 मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थान परिवर्तन इत्यादि के कारण सूची से हटाये गये हैं।

उन्होंने कहा कि उक्त अवधि के दौरान मतदाता सूची से हटाये गये नामों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह इस सम्बन्ध में अपना दावा अपने मतदान क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी अथवा अपने निर्वाचन सभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें ताकि उन पर अपेक्षित कारवाई वाई अमल में लाई जा सके।

प्रवक्ता ने कहा कि मतदाता सूची से हटाये गये नामों की सूचियां राजनैतिक दलों, अपमार्जित मतदाताओं व मृतक के परिवार के परिवार के सदस्यों को सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सूचियां विभागीय वेबसाईट http://ceo himachal.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ हिमाचल मोबाइल एप का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने श्रेष्ठ हिमाचल मोबाइल एप का शुभारम्भ किया। इसके माध्यम से आम लोगों व प्रशासन को अपराध, आपदा, कूड़ा-कचरा, वनो में चोरी अथवा आग,

सड़क दुर्घटनाओं आदि की शिकायतों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से उक्त शिकायतें कर सकेगा। इस एप की विशेषता यह है कि उपयोग कर्ता को अपनी सूचना भेजने से पूर्व किसी भी पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, प्रशासनिक अथवा वन अधिकारी को चयनित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे केवल अपनी शिकायत की श्रेणी को चुनना होगा और फोन के कैमरे के माध्यम से घटना की तस्वीर अथवा स्थान चुनना होगा। इसके आधार पर यह एप उपोगकर्ता को जानकारी देगी कि शिकायत निवारण के लिए किस अधिकारी को चुनना है। फोटो व जीपीएस के माध्यम से स्थान की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी आगामी कार्यवाई करेंगे।

राज्य सरकार के सभी राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों के फोन नम्बर इस एप पर उपलब्ध करवाए गए हैं तथा कोई भी व्यक्ति आसानी से खण्ड स्तर तक के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकेगा।

इस एप को एनआईसी हिमाचल प्रदेश ने विकसित किया है। इस एप को गुगल प्ले स्टोर, हिमाचल सरकार के वैब पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्य सचिव वीसी. फारका जिन्होंने इस एप को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है, भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

महिलाओं की सुरक्षा के लिये एप्प का शुभारंभ

शिमला/शैल। महिलाएं समाज की अभिन्न हिस्सा है, और उनका आदर व सम्मान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है, जिसकी वे हकदार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में सोलन में 'वन स्टॉप सेन्टर' खोला है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा अंचल के तीन जिलों: कांगड़ा, चम्बा तथा ऊना में द्विभाषीय एप्प 'स्त्री सुरक्षा मोबाइल' का शुभारम्भ किया। शिमला से इस एप्प का ऑनलाइन शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एप्प निश्चित तौर पर महिलाओं की आपात स्थितियों में मद्द करेगी।

'स्त्री सुरक्षा मोबाइल' एप्प कांगड़ा की मण्डलायुक्त नन्दिता गुप्ता के दिमाग की उपज है और इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। यह एप्प एण्ड्रॉयड मोबाइल में उपलब्ध है और गुगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। उपयोग कर्ताओं को उनके आवासीय स्थान को चुनना होगा तथा आपातकाल में सूचित किए

जाने के लिए तीन पसंदीदा सम्पर्क नम्बर अंकित करने होंगे। किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन को दबाना होगा। सम्बन्धित जिला चम्बा, ऊना अथवा कांगड़ा के पुलिस नियंत्रण कक्ष को उपयोगकर्ता के जीपीएस स्थान सहित सूचित कर दिया जाएगा। स्थानीय तौर पर, एप्प एक अलार्म उत्पन्न करेगी और स्वत: स्थिति की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी।

नन्दिता गुप्ता ने कहा कि विशेष तौर पर महिलाओं के लिए विकसित की गई एप्प उन्हें संकट अथवा आपात की स्थिति में मद्द करेगी। उन्होंने स्मार्ट फोन की 'सिम्पल टू यूज इन्टरफेस' की सुविधा से महिलाओं की मददगार इस एप्प को विकसित करने के उद्देश्य से अवगत करवाया। जिन महिलाओं के पास स्मार्ट फोन नही है, वे सीधे हैल्पलाईन 181 का प्रयोग कर सकती हैं। परिवहन मंत्री जी.एस. बाली, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविन्द मेहता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बिना विचार कार्य करने वालो को भाग्यलक्ष्मी त्याग देती है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

नकारात्मकता का आरोप बहुत कमजोर तर्क है

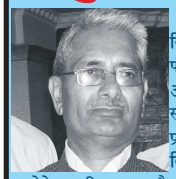

मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों को लेकर छिड़ी बहस का जवाब देते हुए प्रधानमन्त्री ने इन फैसलो के आलोचकों पर नकारात्मकता फैलाने को आरोप लगाया है। लेकिन इसी के साथ यह भी स्वीकारा है कि आर्थिक विकास दर में कमी आयी है। प्रधानमन्त्री ने यह स्वीकारते हुए यह भी दावा किया है कि जल्द ही विकास दर में तेजी आयेगी। इसके लिये उन्होने उनकी सरकार और स्वयं उन पर भरोसा रखने को कहा है। मोदी जी और उनकी सरकार पर 2019 के चुनावों तक आम आदमी के पास उन पर भरोसा रखने के अलावा और कोई विकल्प भी नही है। इस हकीकत को मोदी और आम आदमी दोनो ही समझते हैं। उत्तर प्रदेश पंजाब और उत्तराखण्ड राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद देश पर जीएसटी का फैसला आया है। इस फैसले से देश का हर व्यक्ति/परिवार प्रत्यक्षत: उसी तरह प्रभावित हुआ है जिस तरह आपातकाल के दौरान नसबंदी से लोग प्रभावित हुए थे। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि जीएसटी का प्रभाव नसबंदी से कई गुणा बड़ा है और इसका परिणाम भी उससे बड़ा ही होगा। इन राज्यों के चुनावों से पहले जो नोटबंदी का फैसला आया था उसकी पूरी समझ तो शायद अब तक भी नही आई है। क्योंकि आरबीआई को ही नोटबंदी से जुड़े आंकड़ो को देश के सामने रखने में करीब एक वर्ष का समय लग गया है। यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी जैसे पूर्व मन्त्री भी नोटबंदी के प्रभावों और परिणामों पर अब मुखर हो पाये हैं।

लेकिन जीएसटी के बाद पैट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेण्डर की कीमतों के बढ़ने से हर आदमी इस पर अब रोष में है। ऊपर से केन्द्र के एक मन्त्री का यह ब्यान आना कि मोटर साईकिल और कार चलाने वाला इससे मर नही जायेगा यह दर्शाता है कि मोदी की सरकार और उसके मन्त्री कितने सवेदनशील है क्योंकि इस ब्यान की प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष अमितशाह किसी एक ने भी इसकी निन्दा नही की है। कड़वा सच यह है कि मोदी सरकार आने के बाद खाद्य पदार्थो की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी ही देखने को मिली है। ऐसे में अब यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण यह कीमतें बढ़ी है। क्योंकि पिछले चार वर्षो में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा देश पर नही आयी है जिसके कारण सारे संसाधन नष्ट हो गये हो। उत्पादन बन्द हो गया, सरकार को अपने कोष के दरवाजे आम आदमी को राहत देने के लिये खोलने पड़े हों। इसलिये जब वित्त मन्त्री अरूण जेटली ने यह कहा कि जब सरकारी कोष में पर्याप्त राजस्व आ जायेगा तो उसके बाद जीएसटी की दरों में कमी दी जायेगी। आज केन्द्र राज्यों को पैट्रोल, डीजल पर अपना वैट कम करने के लिये कह रहा है। यदि राज्य सरकारें ऐसा नही करेगी तो फिर इस मंहगाई के लिये राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया जायेगा। जबकि पैट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर इसका हल निकाला जा सकता था। लेकिन केन्द्र ऐसा नही कर रहा है। न ही वित्त मन्त्री ने देश को यह बताया है कि सरकार को कितना राजस्व चाहिए और राजस्व की कमी के लिये कौन जिम्मेदार है क्योंकि सरकारी बैंको के कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों ने जब केन्द्र के बैंक सुधारों को जन विरोधी करार दिया तब उन्होने यह सामने लाया कि जब इस सरकार ने सत्ता संभाली थी तब बैंकों का एनपीए 60 हजार करोड़ था जो अब बढ़ कर 6 लाख करोड़ पहुंच गया है

स्वभाविक है कि सरकारी बैकों के इस बढ़ते एनपीए के कारण नये निवेश के लिये पर्याप्त धन नही है। फिर नोटबंदी से जो लाभ अपेक्षित थे वह मिलने की बजाये उससे केवल नुकसान ही हुआ है। आरबीआई ने देश को यह तो बता दिया कि उसके पास 99% पुराने नोट वापिस आ गये हैं। लेकिन यह अभी तक नही बताया जा रहा है कि कालाधन कितना पकड़ा गया और ऐसे धन के कितने धारकों का कितना नुकसान हुआ है। बल्कि आज अरूण शौरी जैसे पूर्व मन्त्री ने नोटबंदी को सबसे बड़ा मनीलॉडरिंग स्कैम करार दिया है। क्योंकि नोटबंदी से पहले तक स्वामी रामदेव जैसे लोग जो लाखों करोड़ के कालेधन के आंकड़े आये दिन देश को परोस रहे थे वह सब लोग नोटबंदी के बाद इस विषय पर एकदम मौन हो गये है। बल्कि नोटबंदी के माध्यम से आम आदमी की बचत का सारा पैसा बैंको के पास आ गया है। बैंको के पास इस तरह से ज्यादा पैसा आ जाने से बचत पर ब्याज दरों में कटौती कर दी गयी। ऐसे में नोटबंदी से लेकर जनधन खाता योजना और जीएसटी तक के सारे फैसलों से मंहगाई में तो कोई कमी नही आई है। क्योंकि आम आदमी के आंकलन का सबसे सुलभ पैमाना तो मंहगाई ही है। हो सकता है कि इस मंहगाई से सरकारी और नीजि क्षेत्र का कर्मचारी तथा छोटा-बड़ा उद्योगपति, शहर से लेकर गांव तक फैला दुकानदार इतना प्रभावित न हो जितना की आम आदमी। लेकिन इन लोगों का कुल प्रतिशत आय के मुकाबले में अभी तक 25% भी नही है। आज भी देश का 75% आदमी इस मंहगाई और बेरोजगारी से बुरी तरह त्रस्त है। इसलिये आज यह 75% आम आदमी सरकार के आर्थिक फैसलों के गुण दोष परखने लग पड़ा है। वह उसके अनदेखे भविष्य की आस में अपने वर्तमान को बली चढ़ाने के लिये तैयार नही है। उसे बुलेट ट्रेन के फैसले से प्रलोभित कर पाना संभव नही होगा। उसे अपने खेत की उपज का वाजिब दाम और उसे बाज़ार तक लेकर जाने का साधन चाहिये जिसकी उसे दूर- दूर तक आस नही दिख रही है। इसलिये मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों पर उठने वाले सवालों को नकारात्मकता का आरोप लगाकर दबाना संभव नही होगा।

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अग्रसर

राज्य सरकार ने हमेशा ही राज्य के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। हिमाचल प्रदेश को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक वर्ग के विकास को ध्यान में रख कर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कोई कोर – कसर नहीं छोड़ी है।

हिमाचल प्रदेश एक कल्याणकारी और देश में सर्वाधिक विकसित, लोकतांत्रिक तथा खुशहाल राज्य है तथा राज्य के लोगों में मानवीय मूल्यों की कमी नहीं है। आर्थिक, सामाजिक व लिंग आधार पर खुलापन, समानता तथा

समान अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों के समावेश पर सरकार ने विशेष तवज्जो प्रदान की है।

राज्य सरकार ने राज्य में लोकतांत्रिक, न्यायसंगत तथा कल्याणकारी माहौल उत्पन्न किया है। प्रत्येक को समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। लोगों को भी सरकार तथा कल्याणकारी नीतियों पर गहरा विश्वास है। राज्य सरकार अपने नागरिकों के कल्याण की प्राथमिक जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए कृत संकल्प है।

राज्य सरकार ने सुनिश्चित बनाया है कि शारीरिक व मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो तथा उन्हें अन्य लोगों की तरह समाज में सम्मान प्राप्त हो। कल्याणकारी राज्य समाज में विभिन्न तरह से हुए सम्रग विकास के माध्यम से अपने आपको प्रदर्शित करता है। इसी कड़ी में महिलाओं तथा पुरूषों को शिक्षा तथा रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है और राज्य सरकार ने हाल ही में मातृत्व अवकाश को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया है जो पेशेवर व पारिवारिक जीवन में सुगमता लाने में सहायक होगा।

सरकार की सभी नीतियां समानता पर आधारित है और समाज के हर व्यक्ति को अपने जीवन स्तर में सधार लाने व अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए सम्मान अवसर प्रदान किए जा रहे है। कौशल विकास योजना आरम्भ की गई है ताकि युवाओं को अपने कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकें। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के दौरान पात्र युवाओं को 1000 रुपये तथा दिव्यांगों को 1500 रुपये मासिक का भत्ता प्रदान किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते के अर्न्तगत भी पात्र युवाओं को 1000 रुपये तथा दिव्यांगों को 1500 रुपये मासिक का भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

समाज में दिव्यांग लड़के या लड़की से विवाह करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विवाह अनुदान राशि प्रदान की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 40 से 74 प्रतिशत विकलांग लड़का या लड़की से विवाह करने पर 25 हजार रुपये की राशि तथा 75 या इससे अधिक प्रतिशत विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर 50 हजार रुपये के विवाह अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी अनेक छात्रवृतियां प्रदान की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति- जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सुरक्षित व बेहतर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए नए आवास निर्माण के लिए दी जाने वाले अनुदान राशि को 41 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया गया है इस लाभ को प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय सीमा को 17 हाजर रुपये से बढ़ाकर 35 हाजर रुपये किया गया है। अनुसूचित जाति- जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षित आवेदकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दी जाने वाली वित्तीय राशि को 1500 रुपये से बढ़का 1800 रुपये किया गया है इसी प्रकार मिस्त्रियों, बुनकरों व अन्य को उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए 1300 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जा रही है। इनके लिए आय सीमा को 35000 रुपये वार्षिक किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा शिमला जिला के बसंतपुर में 3,66,3900 रुपये की लागत से 50 वृद्धों को ठहरने की क्षमता वाले नए वृद्ध आश्रम निर्माण किया गया है। समाज में सामाजिक समानता तथा अर्न्तजातीय विवाह करने वाले लड़के लड़कियों को 50 हाजर रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, दिव्यांगजनों तथा विधवाओं को 700 रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के प्रात्रा व्यक्यिों को 1250 रुपये प्रति माह की दर से पैंशन प्रदान की जा रही है।

राज्य विधवा एवं विकलांग पैंशन योजना के अन्तर्गत आयु की कोई भी सीमा नहीं है तथा 700 रुपये की मासिक पैंशन विधवाओं को दी जा रही है। योजना में 40 प्रतिशत से लेकर 69 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, जिसकी सालाना पारिवारिक आय 35000 रुपये या इससे कम है, को भी समान राशि की पैंशन दी जा रही है। हालांकि 70 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग व्यक्ति के लिए कोई आय सीमा नहीं है, बशर्ते वह सरकारी/अर्ध-सरकारी/बोर्ड/निगम में कार्यरत न हो अथवा अन्य पैंशन न ले रहा हो। राज्य सरकार कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास भत्ते के रूप में 700 रुपये मासिक भी प्रदान कर रही है, बशर्ते वह सरकारी /अर्ध-सरकारी /बोर्डो निगम में कार्यरत न हो अथवा अन्य पैंशन न ले रहा हो।

बेहतर जल प्रबंधन समय की जरूरत

कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। कहने को तो पृथ्वी चारों ओर से पानी से ही घिरी है लेकिन मात्र 2.5% पानी ही प्राकृतिक स्त्रोतों – नदी, तालाब, कुओं और बावडियों–से मिलता है जबकि आधा प्रतिशत भूजल भंडारण है। 97 प्रतिशत जल भंडारण तो समुद्र में है। लेकिन यह भी एक कडवी सच्चाई है कि भारत जल संकट वाले देशों की लाईन के मुहाने पर खड़ा है। जल के इसी महत्व के मद्देनजर भारत में भी 2012 से सप्ताह भर तक प्रतिवर्ष विचार विमर्श किया जाता है जिसे सरकार ने भारत जल सप्ताह नाम दिया है। इसके आयोजन की जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्रालय को सौंपी गई है। इसकी परिकल्पना भी इसी मंत्रालय ने ही की थी।

अंतरराष्ट्रीय मंच

जल की उपयोगिता, प्रबंधन तथा अन्य जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए यह अंतरराष्ट्रीय मंच बहुत उपयोगी साबित हुआ है, जिसमें देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने जल संसाधन के प्रबंधन और उसके क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के लिए तीन आधारभूत स्तंभों को विशेषज्ञों ने जरुरी माना है – सामाजिक सहयोग, आर्थिक कुशलता और पर्यावरणीय एकरूपता। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि नदियों के थालों (बेसिन) के अनुरूप कार्ययोजना बना कर प्रबंधन किया जाए तथा बेसिन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए। 2012 में हुए पहले मंथन में पांच महत्वपूर्ण सुझाव मिले – खाद्य और ऊर्जा संरक्षण के लिए बेहतर जल प्रबंधन की सहमति बनाई जाए।

जल के प्रभावी और बेहतर उपयोग पर नीति गत चर्चा की जरूरत।

जल परियोजनाओं की वित्तीय और आर्थिक स्थिति के बीच उचित तालमेल पर बल।

जल संसाधनों से जुड़े जलवायु परिवर्तन के ऐसे मुद्दे जिनसे राष्ट्रीय जल मिशन की तमाम गतिविधियां जुड़ी हैं, उन्हें अधिक बढ़ावा देना होगा।

2013 में सात सुझाव मिले जिनमें बेहतर जल प्रबंधन, उसके वित्तीय तथा आर्थिक पहलुओं, बांधों की सुरक्षा और उससे संबंधित कदमों पर कुछ ठोस सुझाव शामिल थे। जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं के मूल्यांकन किये जाने के सुझाव शामिल थे।

2015 से भारत जल सप्ताह के स्वरुप में बड़ा बदलाव आम चुनाव के कारण 2014 में भारत जल सप्ताह नहीं हुआ लेकिन उसके बाद 2015 में आयोजित जल सप्ताह में इसका स्वरूप ही बदल गया। जल से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बात पर आम सहमति रही कि कृषि, औद्योगिक उत्पादन, पेयजल, ऊर्जा विकास, सिंचाई तथा जीवन के लिए पानी की निरंतरता बनाए रखने के लिए सतत् प्रयास की जरूरत है। नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। पहली बार जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विषय वार कार्य योजना बनाने पर भी सहमति बनी। 2016 के भारत जल सप्ताह में विदेशी

विशेषज्ञों की प्रभावी भागीदारी के लिए अन्य देशों को भी शामिल किया गया। 2016 के आयोजन में इजराइल को सहयोगी देश के रुप में शामिल किया गया और उसके विशेषज्ञों ने विशेष रूप से शुष्क खेती जल संरक्षण पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें इजराइल को महारत हासिल है और इस तकनीक में वहां के वैज्ञानिक दुनियाभर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। पिछले साल के आयोजन में भारत सहित 20 देशों के करीब डेढ़ हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कुल आठ संगोष्ठी हुई। दो सत्रों का आयोजन सहयोगी देश इजराइल ने किया था। नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर भी पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुली और विस्तृत चर्चा हुई। जल संसाधन मंत्रालय ने कई सिफारिशों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। कम सिंचाई वाली खेती को बढ़ावा देना और रिसाइकिल्ड पानी का उपयोग कारखानों, बागवानी और निर्माण उद्योग आदि में किया जाने लगा है। कुछ और सिफारिशों को लागू करने की भी तैयारी है

पानी के उचित प्रबंधन की जरूरत इजराइल के मुकाबले भारत में जल की उपलब्धता पर्याप्त है। लेकिन वहां का जल प्रबंधन हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इजराइल में खेती, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में रिसाइकिल्ड पानी का उपयोग अधिक होता है। इसीलिए उस देश के लोगों को पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पडता। भारत जैसे विकासशील देश में 80% आबादी की पानी की जरूरत भूजल से पूरी होती है और इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि उपयोग में लाया जा रहा भूजल प्रदूषित होता है। कई देश, खासकर अफ्रीका तथा खाड़ी के देशों में भीषण जल संकट है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों लोग जबरदस्त जल संकट का सामना कर रहे हैं और असुरक्षित जल का उपयोग करने को मजबूर हैं। बेहतर जल प्रबंधन से ही जल संकट से उबरा जा सकता है और संरक्षण भी किया जा सकता है।

भारत में प्रभावी जल प्रबंधन की जरूरत

भारत में भी वही तमाम समस्याएं हैं जिसमें पानी की बचत कम, बर्बादी ज्यादा है। यह भी सच्चाई है कि बढ़ती आबादी का दबाव, प्रकृति से छेड़छाड़ और कुप्रबंधन भी जल संकट का एक कारण है। पिछले कुछ सालों से अनियमित मानसून और वर्षा ने भी जल संकट और बढ़ा दिया है। इस संकट ने जल संरक्षण के लिए कई राज्यों की सरकारों को परंपरागत तरीकों को अपनाने को मजबूर कर दिया है। देश भर में छोटे – छोटे बांधों के निर्माण और तालाब बनाने की पहल की गयी है। इससे पेयजल और सिंचाई की समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका है। भारत में तीस प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के लगभग दो सौ शहरों में जल और बेकार पड़े पानी के उचित प्रबंधन की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसके कारण सतही जल को प्रदूषण से बचाने के उपाय भी सार्थक नहीं हो पा रहे हैं। खुद जल संसाधन मंत्रालय भी मानता है कि ताजा जल प्रबंधन की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। सीमित जल संसाधन को कृषि, नगर निकायों और पर्यावरणीय उपयोग के लिए मांग, गुणवत्तापूर्ण जल और आपूर्ति के बीच समन्वय की जरूरत है।

नई राष्ट्रीय जल नीति जरुरी

देश में पिछले 70 सालों में तीन राष्ट्रीय जल नीतियां बनी। पहली नीति 1987 में बनी जबकि 2002 में दूसरी और 2012 में तीसरी जल नीति बनी। इसके अलावा 14 राज्यों ने अपनी जलनीति बना ली है। बाकी राज्य तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इस राष्ट्रीय नीति में ''जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसे जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है।'' नीति में जल के उपयोग और आवंटन में समानता तथा सामाजिक न्याय का नियम अपनाए जाने की बात कही गई है। मंत्रालय का कहना है कि भारत के बड़े हिस्से में पहले ही जल की कमी हो चुकी है। जनसंख्यावृद्धि, शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव से जल की मांग तेजी से बढने के कारण जल सुरक्षा के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियां खडी हो गयी है। जल स्त्रोतों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के साथ ही स्वच्छ पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहा है। जल नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा, जैविक तथा समान और स्थाई विकास के लिए राज्य सरकारों को सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के अनुसार सामुदायिक संसाधन के रूप में जल का प्रबंधन करना चाहिए। हालाँकि, पानी के बारे में नीतियां, कानून तथा विनियमन बनाने का अधिकार राज्यों का है फिर भी जल संबंधी सामान्य सिद्धातों का व्यापक राष्ट्रीय जल संबंधी ढाँचागत कानून तैयार करना समय की मांग है। ताकि राज्यों में जल संचालन के लिए जरूरी कानून बनाने और स्थानीय जल स्थिति से निपटने के लिए निचले स्तर पर आवश्यक प्राधिकार सौंपे जा सकें। तेजी से बदल रहे हालत को देखते हुए नयी जल नीति बनाई जानी चाहिए। इसमें हर जरूरत के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता और जल प्रदूषित करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

जल की समस्या, आपूर्ति, प्रबंधन तथा दोहन के लिए सरकारी स्तर पर कई संस्थाऐं काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जल मिशन तथा जल क्रांति अभियान अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण, दुरुपयोग में कमी लाना और विकसित समन्वित जल संसाधन और प्रबंधन द्वारा सभी को समान रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अभियान गांवों और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन, जन जागरण और आपूर्ति के काम में लगा है।

कई देशों में आयोजित होते हैं ऐसे ही कार्यक्रम

पानी के महत्व को सभी देशों ने पहचाना है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका जैसे विकसित देश भी जल सप्ताह आयोजित करते हैं। सिंगापुर में तो यंग वाटर लीडर्स – 2016 के आयोजन में तीस देशों से आए 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पानी के मुद्दे पर गहन चर्चा की। भारत में 10 से 14 अक्तूबर, 2017 के दौरान होने वाले भारत जल सप्ताह – 2017 मे इस बार सहयोगी देश के रूप में हालैंड शामिल हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल क्षेत्र में हालैंड का लाभ भारत को आने वाले दिनों में जरुर मिलेगा।

पसूका

मंत्रिमण्डल के निर्णय

हिमाचल प्रदेश धरोहर पर्यटन नीति स्वीकृत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कृषि कार्यो के लिए ट्रैक्टरों के इस्तेमाल में टोकन टैक्स से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त टोकन टैक्स के बकाया की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है और साथ-साथ ट्रैक्टर प्राप्त

करने के लिए कम से कम एक हैक्टेयर भूमि होने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और यहां की धरोहर को पर्यटक अनुभव कर सकें, इस उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. धरोहर पर्यटन नीति-2017 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य रियासतों से लेकर ब्रिटिश राज तक की धरोहरें, जिसमें भवन, किले, महल, लॉज, हवेलियां, जो किसी न किसी इतिहास से जुड़ी हैं, उनका निरन्तर रख-रखाव करना शामिल है। इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों के नए क्षेत्र विकसित होंगे।

इस नीति का उद्देश्य पर्यटकों को रियासतकाल की जीवनशैली, परम्पराओं और ब्रिटिश काल की वास्तुकला की भव्यता की झलक प्रस्तुत करना और उन्हें यहां के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देना है।

मंत्रिमण्डल ने मनरेगा के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मुरम्मत योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत पंचायतें ग्राम सभा द्वारा सड़कों की मुरम्मत के लिए चुनाव करेंगी और उसके बाद उन्हें मनरेगा में शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत मुरम्मत की गई सड़कों का समय-समय पर सक्षम अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इससे न केवल गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि सड़कों की स्थिति में भी सुधार होगा।

मंत्रिमण्डल ने मनरेगा के तहत लगे 105 कम्प्यूटर ऑपरेटरों, जिन्होंने 31 मार्च,2017 तक तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें पहली जुलाई,2017 से नियमित वेतनमान मनरेगा के प्रशासनिक खर्च से देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने पंचायत चौकीदारों का मानदेय भी 4000 रूपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की।

मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना में तैनात प्रेरकों के लिए पुनर्रोजगार की नीति बनाने का भी बैठक में निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला के उप-मण्डलीय पशु अस्पताल मंगवाइं को क्षेत्रीय पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमण्डल ने निर्वाचन विभाग में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक स्टाफ पैटून/आदर्श संगठनात्मक ढांचा अपनाने को दी मंजूरी।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के नेरवा तथा समरकोट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा किन्नौर जिला के कल्पा तहसील के बारंग में पटवारी के पद सहित पटवार वृत्त सृजित करने को मंजूरी दी।

बैठक में शिमला जिला के रोहडू तहसील के कुटाड़ा में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह निर्माण और सिरमौर जिला के संगड़ाह में उप-मण्डलीय पुलिस कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के रोहडू तहसील के खदराला में पुलिस चौकी खोलने तथा देवता सहिब लक्ष्मी नारायाण नोगली मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में वर्क इन्सपैक्टरों को अतिरिक्त पदोन्नित कोटा उपलब्ध करवाने के लिए भर्ती तथा पदोन्नित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की।

स्वास्थ्य क्षेत्र

पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडिकल कॉलेज चम्बा में स्टाफ नर्सो के 110 पद तथा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सो के अतिरिक्त 13 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने पायलट आधार पर हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के माध्यम से 24 उप केन्द्रों जिनमें से 12 कांगड़ा जिला तथा 12 सिरमौर जिलों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया जिसके लिए आवश्यक स्टाफ सृजित किया जाएगा। मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पांगणा को भी आवश्यक स्टाफ सहित समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करने को दी मंजूरी।

बैठक में शिमला जिला की चौपाल तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मड़ावग को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और चौपाल तहसील के संगरोली (बमटा) में आवश्यक स्टाफ सृजित करने सहित उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी दी।

कुल्लू जिला के कसोल में आवश्यक स्टाफ सहित स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में मण्डी जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र सलोट को आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया है। कांगड़ा जिला की रक्कड़ तहसील के बन्नी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उप दवा नियंत्रक का एक पद सृजित करने को मंजूरी दी। मण्डी जिला के थलाटुखोड पशु औषद्यालय तथा लाहौल स्पिति जिला के घीयु पशु औषद्यालय को पशु अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत किया गया है जिसके लिए आवश्यक स्टाफ का सृजन किया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के राजकीय महाविद्यालय नेरवा में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से अंग्रेजी तथा वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया।

शिमला जिला के नेरवा शिक्षा खण्ड की ग्राम पंचायत किरण के फाजियाबाग में प्राथमिक स्कूल खोलने तथा सोलन जिला के राजकीय प्राथमिक सतरोल को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, दंरग विधानसभा क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शरआना तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसडेहरा को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में नवसृजित नेरवा तहसील के राजकीय उच्च पाठशाला कुठार को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

कांगड़ा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढ़ियार का पुनः नामकरण कर बख्शी प्रताप सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढ़ियार करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कोठीपुरा में रखी एम्स की आधारशिला

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र के साथ बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में खुलने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखने की रसम अदा की। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

1351 करोड़ रुपये के परिव्यय से निर्मित किया जाने वाला एम्स हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करेगा। लोगों को वृहद चिकित्सा जांच

तथा विभिन्न गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वापस राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई 205 एकड़ भूमि में एम्स के निर्माण का प्रस्ताव है। वीरभद्र सिंह एम्स की आधारशिला रखने में हुई देरी को लेकर काफी चिन्तित हैं क्योंकि उन्होंने कई बार इस मामले को लेकर अपनी चिन्ता जाहिर की और राज्य में इस प्रतिष्ठित संस्थान को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री से बार-बार आग्रह किया है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के लोगों को सुकून प्रदान करने के लिए संस्थान निकट भविष्य में शीघ्र बनेगा और इसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसका निर्माण शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया ताकि लोगों को उनके घरद्वार के समीप गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। आरम्भ में, एम्स में 750 बिस्तरों की क्षमता के बीस सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक होंगे। संस्थान में हर वर्ष प्रत्येक बैच में एमबीबीएस की 100 सीटें तथा नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। परिसर के अन्दर सभी विभाग वाणिज्यिक व आवासीय क्षेत्र से जुड़े होंगे।

प्रधानमंत्री ने ऊना जिला के सलोह में स्थापित किए जाने वाले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की आधारशिला रखी। आईआईआईटी के निर्माण के लिए राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014 में 60 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। आईआईआईटी का निर्माण 128 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। भारत सरकार लागत का 50 प्रतिशत जबकि राज्य सरकार 35 प्रतिशत खर्च वहन करेंगी और शेष 15 प्रतिशत हि.प्र. ऊर्जा निगम तथा हि.प्र. ऊर्जा ट्रांसमिशन निगम उद्योग भागीदारों द्वारा वहन किया जाएगा।

आरम्भ में आईआईआईटी में तीन पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं और कक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2014-15 से एनआईटी हमीरपुर में शुरू की गई थी। 160 की वार्षिक क्षमता के साथ इन पाठयक्रमों में कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। यह देश का 20वां आईआईआईटी हैं।

प्रधानमंत्री ने कांगड़ा जिला के कन्दरोड़ी में 70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस्पात प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया इसमें हर वर्ष एक लाख टन इस्पात उत्पादन की क्षमता होगी। इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने वर्ष 2014 में शुरू किया था। इससे राज्य के युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

उन्होंने गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा देख-भाल के लिए बिलासपुर तथा कुल्लू जिला के लिए टाटा डिजिटर नर्ब सैंटर की भी शुरूआत की। यह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देख-भाल की सुविधा प्रदान करेगा। टाटा परामर्शी सेवाओं की पहल डिजिटल नर्ब केन्द्र देशभर में 15 मिलियन लोगों तक पहुंची है। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के लूहणू हैलीपैड में प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया।

नौजवान पीढ़ी का नशे की लत से क्यायें:धूमल

हमीरपुर/शैल। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊहल कस्बे के परनाली गाँव में विश्व शांति कल्याण के लिए एवम नियंत्रण रेखा पर आज तक प्राण न्योछावर करने वाले हजारों सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए विशाल गायत्री महायज्ञ का शुभारम्भ करने के उपरान्त पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने उपस्थित श्रधालुओं व स्थानीय ग्रामवासियों को सम्बोधित किया।

प्रो. धूमल ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि यह अनुष्ठान एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए नहीं अपितु राष्ट्र हित में किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका लाभ मानव समाज को होगा। ऐसे अनुष्ठानों में सभी को योगदान देना चाहिए। क्योंकि सीमा पर तैनात जवान, जो आज भी अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए किये जा रहे प्रयास हैं, इससे पवित्र कार्य कोइ नहीं हो सकता। हम सब इस लिए यज्ञ यहाँ कर पा रहे हैं क्योंकि सीमा पर खड़े सैनिक कहीं माईनस चालीस डिग्री तो कहीं प्लस चालीस डिग्री तापमान में अपन कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसे पुण्य कार्य करने की सद्बुद्धि भगवान तभी देता है जब आप पुण्य कार्यो की ओर समर्पित हों।

प्रो. धूमल ने कहा कि धार्मिक कार्यो का सबसे बड़ा लाभ यह है की जो बच्चा यहाँ आएगा और धार्मिक कार्यो में लगेगा वह नशों से दूर रहेगा। आज समाज में कुछ लोग ऐसे धार्मिक कार्यो में समय लगा रहे हैं और कुछ लोग नौजवान पीढ़ी को नशा बाँट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे के आदि हो चुके हैं। चीन-पकिस्तान के हमलों से कौन डरता है, कई बार लड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन घर में नशे की लत में फंसे बच्चे ज्यादा चिंतनीय विषय हैं, क्योंकि हालत तब पता चलती है जब सब हाथ से निकल चुका होता है। ऊना के एक विधानसभा क्षेत्र में अठाईस नौजवान बच्चे नशे की लत के कारण मारें हैं। नशे के व्यापारी बड़े लोगों के सरंक्षण में मौत बाँट रहे हैं। इसलिए सबको अपने आस पास सचेत रहना चाहिए। नशे की लत से सबको बचना चाहिए। लत डालो मगर भगवान् के नाम की, सेवा की और समर्पण की।

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के दूरदर्शी कुशल मार्गदर्शन में

शानदार उपलब्धियों के 5 साल

अवार्ड सम्मान

- शिक्षा एवं समग्र विकास में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य।
- देशव्यापी सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ स्थान के लिए देश के छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम आंका गया।
- मीडिया स्टडीज केंद्र द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में हिमाचल को देश का सबसे "ईमानदार" राज्य आंका गया।
- बड़े राज्यों में प्रथम खुला शौचमुक्त राज्य घोषित, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कृषि कर्मण्य अवार्ड।

शिक्षा

- 1485 नए स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए। 54 नए डिग्री कॉलेज खोले तथा 6 निजी कॉलेजों को सरकार ने अपने अधीन लिया।
- नए खुले महाविद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 900 पद तथा शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 9600 पद भरे।
- तीन इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय पोषित संस्थान जैसे आई. आई. टी., आई. आई. एम., आई. आई. आई. टी. तथा आर.बी.टी. आई खोले।

स्वास्थ्य

- 230 नए स्वास्थ्य संस्थान खोले।
- ई. एस. आई. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक का सरकार ने किया अधिग्रहण। मेडिकल कॉलेज सिरमौर, चम्बा और मण्डी में 100 एम. बी. बी. एस. की सीटों में कक्षाएं आरम्भ। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य प्रगति पर।

समाज कल्याण

- सामाजिक सुरक्षा पैंशन 450 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह की। 4 लाख पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पैंशन का उठा रहे लाभ।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 1200 रु मासिक पैंशन।

बेरोज़गारी भत्ता

- 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए बेरोज़गारी भत्ता योजना लागू। पात्र युवाओं को 1000 रुपये तथा दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता। 18.09.2017 तक 16936 युवाओं को 3 करोड़ 46 लाख रु से अधिक का बेरोज़गारी भत्ता वितरित।

कौशल विकास

- युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना आरम्भ। पात्र युवाओं को 1000 रुपये तथा शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह भत्ता।
- 31.08.2017 तक 156 करोड़ रु खर्च तथा 1,84,387 युवा लाभान्वित।

सबका कल्याण

- 31 मार्च, 2017 तथा 30 सितम्बर, 2017 को 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जा रहा है, जिससे 40,000 कर्मचारी लाभान्वित।
- 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले दिहाड़ीदारों को नियमित किया जा रहा है। 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले अंशकालिक कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जा रहा है।

सड़क व परिवहन

- 2314 कि.मी. नई सड़कों व 215 पुलों का निर्माण कर 864 गाँव को सड़कों से जोड़ा।
- परिवहन निगम के बेड़े में 1615 नई बसें शामिल। 69 सुपर स्पेशियलिटी वोल्वो स्कैनिया तथा 20 लग्जरी बसें कर रही प्रदान परिवहन सुविधा।

औद्योगिक विकास

- प्रदेश में 5488.48 करोड़ रुपये के निवेश से 4401 औद्योगिक इकाइयां स्थापित, जिनमें 62,351 युवाओं को रोज़गार मिला। सरकारी क्षेत्र में 63000 युवाओं को मिला रोज़गार।
- नए उद्योगों की स्वीकृतियाँ एक ही आवेदन पर 45 दिनों के भीतर।
- ऊना की पंडोगा में 150 करोड़ व कांगड़ा के कन्दरोड़ी में 122 करोड़ की लागत से स्टेट-ऑफ-द-आर्ट औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास।

हिमाचल वासियों की सुविधा का हम रखते हैं ध्यान

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस का विकास के सहारे विजय का दावा

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार **''विकास से विजय''** रैली आयोजित करके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष प्रदेश में हुए विकास की जो तस्वीर सामने रखी है उससे आश्वस्त और आशान्वित हो करे राहुल ने दावा किया है कि वीरभद्र सातवीं बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री बनेंगे। इस रैली में सरकार ने इस कार्यकाल में हुए विकास के आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं और यह रखने के लिये इस रैली के आयोजन पर हुआ सारा खर्च सरकार ने उठाया है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा कभी भी संभावित है ऐसे में इस समय सरकारी खर्च पर अपने विकास की उपलब्धियां जनता के सामने रखना राजनीतिक दृष्टि से कितना सही फैसलो सिद्ध होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि 2012 में धूमल भी इसी विकास के नाम पर सत्ता में वापसी के दावे कर रहे थे और उस समय उनके पास विकास के नाम पर मिले सौ से अधिक अवार्डों का तमगा भी था लेकिन फिर भी जनता ने उन्हे मौका नही दिया। क्योंकि कांग्रेस ने उनके साथ **''हिमाचल ऑन सेल''** का ऐसा आरोप चिपका दिया जिसे भले ही सत्ता में आकर कांग्रेस प्रमाणित नही कर पायी है। लेकिन उस समय यह आरोप विकास पर भारी पड़ गया था यह सबके सामने है।आज कांग्रेस और वीरभद्र सरकार ठीक उसी स्थिति में खड़ी है।

विकास एक ऐसा विषय है जिसे सवालों के घेरे में खड़ा करना बहुत आसान होता है। जैसे आज केन्द्र की मोदी सरकार को जुमलों की सरकार करार दिया जाने लग पड़ा है क्योंकि इस सरकार के सारे आर्थिक फैसलें मोदी-जेटली के दावों के वाबजूद जनता की नज़र में नुकसान देह साबित हुए हैं और इसी आधार पर राहुल और कांग्रेस मोदी पर हमलावर हो रही है। ठीक इसी तरह आज जब इस विकास के इन आंकड़ो को प्रदेश के बढ़ते कर्ज के आईने में देखा जायेगा तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखेगी। यह ठीक है कि आज उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो पर 1656.86 करोड़ का निवेश हुआ है और मुख्यमन्त्री के अपने क्षेत्र शिमला ग्रामीण में हुई 20% घोषणाओं पर करीबे 1200 करोड़ का निवेश हुआ है। यह सारा निवेश अमली जामा भी पहन चुका है। विकास के नाम पर यह क्षेत्र आज प्रदेश के माडल हैं लेकिन क्या ऐसा ही निवेश प्रदेश के शेष 66 विधानसभा क्षेत्रों में भी हुआ है यह सवाल आने वाले दिनों में उठेगा। फिर जो संस्थान खोले गये हैं क्या उनमें सुचारू रूप से कार्य करवाने की सुनिश्चितता बन पायी है। क्योंकि जब एक संस्थान से कुछ कर्मचारियों को दूसरे संस्थान में बदल कर नये का काम चलाया जाता है तब दोनों में ही कुछ व्यवहारिक कमीयां रह जाती हैं और परिणाम स्वरूप दोनों जगह नाराज़गी उभर आती है। यदि नये खोले संस्थानों में नयी भर्तीयां करके कर्मचारी नियुक्त किये जाएं तब ऐसी नियुक्तियां करने में न तो पूरा समय उपलब्ध हो पाता है और न ही पूरी प्रक्रिया हो पाती है और ऐसे चयनों पर पक्षपात के आरोप लगने स्वभाविक हो जाते हैं। इसलिये आज विकास के दावों पर सरकारों का बनना सदिग्ध हो जाता है। फिर सरकार तो होती ही विकास के लिये है और उस पर लगने वाला पक्षपात का एक भी आरोप सारे दावों की हवा निकाल देता है।

कांग्रेस जहां **''विकास से विजय''** को सहारा बना रही है वहीं पर भाजपा कांग्रेस से **''हिसाब मांगे हिमाचल''** के तहत लगातार हमलावर होती जा रही है। भाजपा के इन हमलों का जवाब जब तक कांग्रेस उसी तर्ज में देने को तैयार नही होगी तब तक उसके विकास के दावों का असर हो पाना संभव नही लगता है। भाजपा लम्बे अरसे से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर व्यक्तिगत स्तर पर हमलावर होने की रणनीति पर काम करती आ रही है। वीरभद्र सिंह के अतिरिक्त भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु पर भी निशाना साध चुकी है। सुक्खु ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर मानहानि का मामला दायर करने का दावा किया था जो आज तक पूरा नही हुआ है। सूत्रों की माने तो अब इस कड़ी में और भी बहुत कुछ जुड़ने वाला है। भाजपा के निशाने पर वन मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी, उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री और शहरी विकास मन्त्री सुधीर शर्मा विशेष रूप से रहने वाले हैं। कांग्रेस मण्डी रैली में आक्रामक होने की बजाये रक्षात्मक रही है ऐसे में अब इस पर निगाहें लगी है कि क्या कांग्रेस इसी रक्षात्मक तर्ज पर आगे बढ़ेगी या आक्रामक होने का साहस दिखायेगी ।

ब्रेकल के खिलाफ एफआईआर क्यों नही

3000 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार कौन?

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2006 में छः हजार करोड़ के निवेश वाली जंगी-थोपन-पवारी हाईडल परियोजना के लिये निविदायें आमन्त्रित की थी। निविदायें आने के बाद यह परियोजना हालैण्ड की कंपनी ब्रेकले कारपोरेशन को आवंट की दी गयी। आंवटन के बाद नियमों के अनुसार कंपनी को 280 करोड़ का अपफ्रन्ट प्रिमियम सरकार में जमा करवाना था। लेकिन यह कंपनी यह पैसा समय पर जमा नही करवा पायी और सरकार से किसी न किसी बहाने समय मांगती रही। जब ब्रेकल यह प्रिमियम अदा नही कर पायी तब इसी आंवटन की प्रक्रिया में दूसरे स्थान पर रही रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इस मामलें को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। यह चुनौती दिये जाने के बाद सरकार में भी ब्रेकल के दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू हो गयी और अपराधिक मामला दर्ज करने की नौबत आ गयी। ब्रेकल को सरकार ने यह आवंटन रद्द करने का नोटिस दे दिया। नोटिस मिलने के बाद ब्रेकल ने अदानी से 280 करोड़ लेकर सरकार में प्रिमियम जमा करवा दिया और सरकार ने इसे ले भी लिया। इससे रिलांयस की याचिका निरस्त हो गयी। सरकार ब्रेकल को नोटिस दे चुकी थी विजिलैन्स ने अपराधिक मामला दर्ज किये जाने की संस्तुती सरकार को भेज रखी थी। इस पर सरकार ने पूरा मामला सचिव कमेटी को फिर से जांच के लिये भेज दिया। सचिव कमेटी ने ब्रेकले को तलब किया और ब्रेकल के साथ ही अदानी के अधिकारी भी कमेटी में पेश हो गये जबकि उनके आने का कोई कानूनी आधार नही था। लेकिन सचिव कमेटी ने उनकी उपस्थिति पर कोई एतराज नही जताया और यह परियोजना फिर ब्रेकल को ही देने का फैसला कर दिया।

रिलांयस ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। रिलांयस के साथ ही ब्रेकल भी अपना

पक्ष लेकर सवोच्च न्यायालय में पहुंच गया। इन्ही के साथ ही अदानी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में यह पक्ष रख दिया कि 280 करोड़ निवेश उसने किया है इस पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो गया। इस नोटिस पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में अपना जवाब दायर करते हुए अदालत के सामने यह रखा कि इस परियोजना में हुई देरी से सरकार को 2775 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके लिये ब्रेकल को इस नुकसान की भरपायी करने तथा अपफ्रन्ट प्रिमियम के नाम पर आये उसके 280 करोड़ जब्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार का यह स्टैण्ड अदालत में आने के बाद ब्रेकल ने अपनी याचिका वापिस ले ली। ब्रेकल के याचिका वापिस लेने के साथ ही अदानी की याचिका भी निरस्त हो गयी। लेकिन यह होने के वाबजूद आज तक सरकार ने 2775 करोड़ वसूलने के लिये कोई कदम नही उठाये हैं यहां तक कि प्रिमियम के आये 280 करोड़ भी अब तक जब्त नही किये गये हैं।

बल्कि इसमें सबसे दिलचस्प तो यह घटा कि ब्रेकल और अदानी के सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आते ही रिलांयस और सरकार में कुछ घटा तथा यह परियोजना फिर से रिलांयस को देने का फैसला कर दिया गया। रिलांयस को इस आश्य का पत्र भी चला गया। रिलांयस ने इस पत्र को स्वीकार करवाने में सहयोग करने का आग्रह कर दिया। रिलांयस को यह सब हासिल करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापिस लेनी थी। इसका सरकार के साथ मिलकर सयुंक्त आग्रह अदालत में जाना था। इसके लिये सरकार पहले तैयार हो गयी लेकिन बाद में मुकर गयी। दूसरी ओर जब अदानी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आया तो उसने अपने 280 करोड़ वापिस किये जाने के लिये सरकार को पत्र लिखा। इस पत्र का असर यह हुआ कि जब रिलायंस को यह प्रौजेक्ट देने का फैसला लिया गया तब यह मान लिया गया कि रिलायस से प्रिमियम आने के बाद अदानी के 280 करोड़ वापिस कर दिये जायेंगे। अब रिलांयस भी पीछे हटने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर ने निदेाक एनर्जी को पत्र लिखकर यह राय मांगी है कि क्या इस परियोजना को फिर से ब्रेकल को दिया जा सकता है या इसकी फिर से बोली लगायी जाये या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम को दे दिया जाये। अभी तक सरकार कोई फैसला ले नही पायी है लेकिन अदानी के 280 करोड़ वापिस करने के लिये दो बार यह मामला मन्त्री परिषद की बैठक में रखा जा चुका है लेकिन वहां भी फैसला नही हो पाया है।

स्मरणीय है कि यह परियोजना 2006 से अधर में लटकी हुई है। ब्रेकल ने जिन दस्तावेजो के सहारे यह आवंटन हासिल किया था वह जांच में सही नही पाये गये और विजिलैन्स ने इस पर ब्रेकल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति अभी तक निदेशक एनर्जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव और विधि विभाग के बीच लटका हुआ है जबकि विधि विभाग स्पष्ट कह चुका है कि यह फैसला विभाग को अपने स्तर पर लेना है क्योंकि नुकसान उसका है सरकार स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में कह चुकी है। कि इसमें 2775 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इसकी भरपायी के लिये नोटिस जारी कर दिया गया है। ब्रेकल सर्वोच्च न्यायालय से मामला वापिस ले चुका है इससे ब्रेकल के खिलाफ आपरधिक कारवाई करने का रास्ता तलाशा जा रहा है। इस मामले में धूमल शासन और वीरभद्र शासन दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं क्योंकि धूमल शासन में भी रिकवरी के लिये कोई नोटिस जारी नही हुआ था।

सरकार की हैरिटेज

.....पृष्ठ 1 का शेष

तंवर ने कहा कि उनकी पार्टी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के खिलाफ नहीं है लेकिन मेहनतकश जनता की समृद्ध विरासत को नजरअंदाज करना सही नहीं है।

तंवर ने कहा कि सरकार अगर पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे पर्यटन स्थलों को बेहतर ढंग से विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी के नजदीक ही कुफरी पर्यटन स्थल है जिसके साथ आसपास की पंचायतों बणी, चियोग, सतोग, दरभोग, कुफरी, पटगैहर आदि पंचायतों के कम से कम 2000 लोगों का रोजगार जुड़ा है लेकिन सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और न ही इसे विकसित करने की योजना बनाई।

उन्होंने कहा कि अपने महलों को सरकारी खजाने से संवारने के बजाय सरकार को चाहिए कि वह हमारे कारीगरों और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए एक ठोस योजना तैयार करे ताकि वे अपनी आजीविका के लिए दर-दर भटकने को मजबूर न हो।